दैनिक जागरण

पाप मूलत: ईश्वर से विमुख होना है

बेकाबू पाकिस्तान

पाकिस्तान की हरकतों से यह साफ है कि उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह दुनिया को इसके लिए कैसे समझाए कि कश्मीर को लेकर उसकी ओर से जो कुछ कहा जा रहा है वह सही है। वास्तव में इसी कारण वह छल-कपट के साथ झूठ का सहारा लेने में लगा हुआ है। चूंकि वह एक जिम्मेदार राष्ट्र की तरह व्यवहार करने से इन्कार कर रहा है इसलिए भारत को उससे निपटने के लिए कुछ नए तौर-तरीके अपनाने होंगे। कश्मीर पर हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर मात खाने के बाद उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती दिख रही हैं। उसने भारत को कुलभूषण जाधव से दोबारा संपर्क-संवाद करने की राजनयिक सुविधा देने से इन्कार करके यही स्पष्ट किया कि उस पर नए सिरे से दबाव बनाने की जरूरत है। यह करीब-करीब तय है कि वह आसानी से सही रास्ते पर आने वाला नहीं है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं कि कुलभूषण जाधव को राहत दिलाने और उन तक अपनी राजनयिक पहुंच स्थापित करने के लिए भारत की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान झूठ पर जीने वाला एक असामान्य देश है। उसे न तो अपनी छवि की परवाह है और न ही प्रतिष्ठा की। इसीलिए वह एक ओर जहां कश्मीर को अशांत करने के लिए आतंकियों की घुसपैठ में जुटा है वहीं दूसरी ओर अपनी जनता को उकसाने में भी लगा हुआ है। वह यह काम इसीलिए कर रहा है ताकि अपने लोगों का ध्यान उन समस्याओं से हटाया जा सके जिनसे वह बुरी तरह त्रस्त है।

अब जब यह और अधिक स्पष्ट है कि सेना के वर्चस्व वाला पाकिस्तान कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है तब फिर भारत को उसे कठघरे में खड़ा करने, उसके झूठ को बेनकाब करने और उसे चेताने के अलावा भी कुछ करना होगा। यह कोई बेहतर स्थिति नहीं कि भारत पहले की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करता हुआ अथवा अपनी सीमाओं की चौकसी बढ़ाता हुआ दिखे। निःसंदेह मोदी सरकार ने एक झटके में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर और उसे नए सिरे से गठित करके पाकिस्तान के होश उड़ा दिए, लेकिन जब यह दिख रहा है कि वह सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तब फिर इसके अलावा और कोई उपाय नहीं कि उसके खिलाफ कुछ और कदम उठाए जाएं। ये कदम ऐसे होने चाहिए जिससे उसे यह अहसास हो सके कि वह आतंक का सहारा लेकर भारत को तंग नहीं कर सकता। यह मान लेना सही नहीं होगा कि जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त करके पाकिस्तान पर काबू पा लिया गया है।

बदलता झारखंड

वनों से आच्छादित झारखंड की पहचान यहां के झाड़-जंगलों और खनिज संपदा से ही अब तक होती रही है। लेकिन हमारा झारखंड अब बदल रहा है। आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। झारखंड का नया भव्य विधानसभा भवन और साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल के शुभारंभ को बानगी के तौर पर लिया जा सकता है। झारखंड गठन के 19 साल बाद तक राज्य का अपना विधानसभा भवन तक नहीं था, किराए के भवन में संचालित हो रहा था। अब राज्य के लोगों को लोकतंत्र का यह मंदिर मिल गया है। शुक्रवार को इस नए भवन में एक दिन का विशेष सत्र भी आयोजित होगा। निश्चित तौर पर यह राज्यवासियों के लिए गौरव की बात है। सचिवालय के नए भवन का भी खाका तैयार किया गया है। 1238 करोड़ रुपये की लागत से भव्य भवन का निर्माण किया जाएगा। साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल ने राष्ट्रीय जलमार्ग का नया इतिहास लिखा है। छह अप्रैल 2017 को इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार इस टर्मिनल का उद्घाटन भी उन्होंने ही किया। यह पूरे झारखंड विशेषतौर पर संताल परगना के लिए विकास के नए द्वार खोलेगा। व्यापार तो सुगम होगा ही, नए रोजगार का सृजन भी होगा। बदलते झारखंड की विकास गाथा यहीं खत्म नहीं होती। उज्ज्वला योजना ने गरीब महिलाओं के आंखों के आंसू पोछे हैं। स्वच्छता मिशन से खुले में शौच से मुक्ति मिली है। गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। आयुष्मान योजना ने गरीबों को महंगे इलाज से मुक्ति दिलाई है। जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों के लिए देशभर में 462 मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, उनमें 69 सिर्फ झारखंड में खुलेंगे। यहां जनजातीय बच्चों को न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उनकी खेल प्रतिभाओं को भी निखारा जाएगा। जाहिर है झारखंड बदल रहा है, लेकिन यह बदलाव तभी सार्थक है जब हम बदलते देश और दुनिया की तरह अपने विचारों में भी परिवर्तन लाएं। तभी वास्तव में नए और आधुनिक झारखंड का निर्माण होगा।

> झारखंड बदल रहा है, लेकिन यह परिवर्तन तभी सार्थक होगा जब हम बदलते देश और दुनिया की तरह अपने विचारों में भी परिवर्तन लाएं

हिंदू-मुस्लिम संवाद का सही आधार

शंकर शरण

दोतरफा और खुले संवाद का राजनीतिक ही नहीं, शिक्षात्मक मूल्य भी है। इससे हिंदू-मुसलमान, दोनों पक्षों के भ्रमित लोग सीखते हैं

हाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत से जमीयत उलेमा-ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी मिलने गए। इस मुलाकात ने देश का ध्यान खींचा और उस पर व्यापक चर्चा हुई। इस मुलाकात के बाद जमीयत उलेमा-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने इस बारे में मीडिया को बताया कि भीड़ की हिंसा, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जैसे विषयों पर बात हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जमीयत सावरकर और गोलवलकर के विचारों से सहमत नहीं है। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रवक्ता की ओर से बयान आया कि संघ राष्ट्रीय एकता और शांति के लिए काम करता है और जो भी इसमें भाग लेना चाहे उसका स्वागत है। स्वभावतः मदनी के बताए बिंदुओं पर मीडिया में कुछ ऐसी टिप्पणियां आईं जिससे यह संदेश उभरा कि मुस्लिम पक्ष पीड़ित और अन्य पक्ष उत्पीड़क है। आखिर ऐसा संदेश उभरना या फिर उभारा जाना कहां तक उचित है? क्या हिंदुओं को जिहाद, बलात या छलपूर्वक धर्मांतरण एवं अन्य मतवादी गतिविधियों से कोई शिकायत नहीं? क्या कश्मीर में अलगाववाद, मजहबी कट्टरता, लव-जिहाद, कैराना जैसी गतिविधियां, संयुक्त राष्ट्र को भारत सरकार के विरुद्ध चिट्ठी लिखना सही है? ऐसी मुलाकातों का एकतरफा और गलत संदेश जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह देशहित दृष्टि से भी अनुचित है कि पीड़ित को उत्पीड़क बताया जाए और उसका प्रतिवाद भी न हो। मौलाना मदनी ने संवाद का उपयोग एक तरह से हिंदुओं और सरकार पर आरोप लगाने में किया, जबकि हिंदुओं की शिकायत पर कोई बात न हुई। इससे राष्ट्रीय एकता या शांति नहीं बन सकती। इसमें गांधीजी के विफल प्रयास हमारे लिए एक सबक हैं। उनकी सद्भावना के बावजूद उनके तरीकों और उनकी नीतियों ने उलटे परिणाम दिए।

राजनीति में एकतरफापन कभी द्विपक्षीय भलाई नहीं करता। हिंदू-मुस्लिम संवाद चलाने का सही आधार हमें स्वामी विवेकानंद, रवींद्रनाथ टैगोर, श्रीअरविंद जैसे मनीषियों की शिक्षाओं में मिलता है। संवाद करने वाले की मनोवृत्ति के अनुरूप संवाद होना चाहिए। एक पक्ष केवल अपने मतवाद, विशेषाधिकार की जिद रखे तो दूसरे को उसकी गलती बतानी-दिखानी चाहिए। इस पर चुप्पी से उसे कमजोर या गाफिल समझा जाता है। फलतः दूसरा पक्ष अपनी मांग बढ़ाता जाता है। गांधीजी ने यही गलती की थी। वह यह देख ही नहीं सके कि उनकी उदारता को दूसरा पक्ष कैसे ले रहा है? इस गफलत का खामियाजा हिंदुओं के संहार और बर्बादी से देना पड़ा।

राष्ट्रीय एकता या सामाजिक सद्भाव बराबर की जिम्मेदारी है। इसमें तनिक भी मुरव्वत नुकसानदायक है। श्रीअरविंद ने कहा था, 'हिंदू-मुस्लिम एकता का अर्थ हिंदुओं को नीचे रखना नहीं होना चाहिए। हम झूठे संतोष में आराम करने लगते हैं कि हमने एक कठिन समस्या का समाधान कर लिया है, जबकि वास्तव में हमने केवल उसे टाला भर है।'

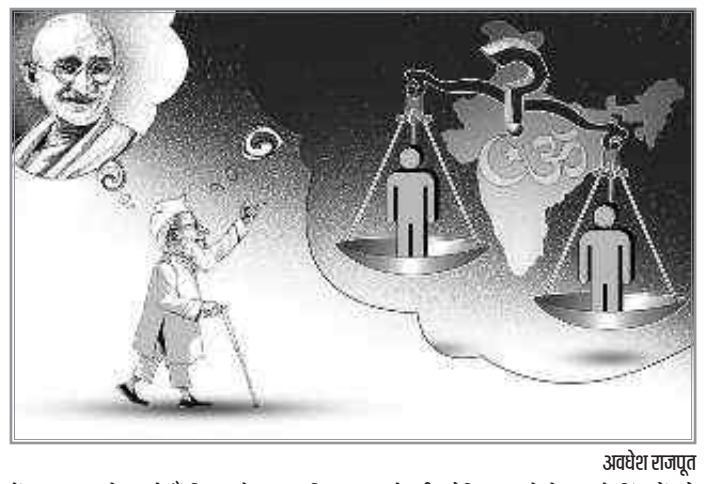

अवधेश राजपूत

हिंदुओं की शिकायतों को स्पष्ट रखने से मुस्लिम पक्ष पर भी स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी आती है। वह न्याय-भावना का दबाव महसूस करता है। जनमत की भी चिंता करता है। दोतरफा और खुले संवाद का राजनीतिक ही नहीं, शिक्षात्मक मूल्य भी है। इससे हिंदू-मुसलमान, दोनों के भ्रमित लोग सीखते हैं। उन्हें पता चलता है कि दोनों पक्ष की मांगे, शिकायतें क्या हैं? एकतरफा शिकायतबाजी तो मामले को और विकृत बनाती है।

गांधीजी ने हिंदुओं पर 'अधिक जिम्मेदारी' की गलत कल्पना की थी। उसका कुफल हिंदुओं को उठाना पड़ा, जबकि टैगोर ने दो-टूक कहा था कि हिंदुओं का सामाजिक बल कमजोर और मुसलमानों का मजबूत है। इसे समान बनाए बिना कभी शांति नहीं हो सकती। श्रीअरविंद ने भी मुसलमानों को तुष्ट करने के प्रयास को मिथ्या कूटनीति बताया था। उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता उपलब्ध करने की कोशिश करने के बदले हिंदुओं को सच्चे राष्ट्रीय कार्य में लगने के लिए कहा था, जिसमें विवेकशील मुसलमान धीरे-धीरे स्वयं जुड़ जाते, लेकिन 'एकता का पैबंद लगाने की कोशिश ने मुसलमानों को अहमियत दे दी और यही सारी आफतों की जड़ रही।' हमें यह सबक कभी नहीं भूलना चाहिए। एक विदेशी विद्वान कोएनराड एल्स्ट ने गांधीजी की एकतरफा उदारता को 'हिंदू अहंकार' कहा है। गांधी ने अपने को अधिक जानकार, अधिक उत्तरदायी नेता समझा और मुसलमानों को अज्ञानी, जिद्दी बच्चे जैसा मानकर व्यवहार किया। यह भयंकर भूल थी।

हमारे मनीषियों ने साफ कहा था कि ''मुसलमानों को भारत माता की समान संतान समझते हुए, हर तरह से, सच्चे हृदय से समानता का व्यवहार करो। यदि वे भाई की तरह मिलना चाहें तो और पहलवान की तरह लड़ना चाहें तो दोनों स्थितियों में।'' गांधीजी ने इसकी उपेक्षा करते हुए उच्च-भाव से व्यवहार किया, जिस कारण भारी हानि हुई। यदि वार्ता हो तो वह बराबरी से एवं न्यायोचित हो, किंतु यदि एक पक्ष जबरन कुछ छीनना चाहे तो दूसरे को लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लड़ने से बचना हीन व्यवहार का प्रमाण था, जिसे गांधीजी उदारता समझ बैठे। यह भगवद्गीता की शिक्षा के विरुद्ध था। फलतः दूसरे पक्ष ने उससे अपना अर्थ निकाला। यह सब विषम व्यवहार का दुष्परिणाम था।

गांधीजी के नरमी दिखाने और झुकने वाले रुख पर श्रीअरविंद ने सटीक टिप्पणी की थी कि ऐसे रवैये से तो मुस्लिम पक्ष को यही संकेत मिलेगा कि उसकी मनचाही होती जाएगी। मुस्लिम नेताओं के साथ सच्चा हिंदू व्यवहार निर्भयता, समानता और सत्य-निष्ठा से ही हो सकता था। परंतु अनुचित बातों पर चुप्पी, छूट, दिखावा, दोहरापन और 'रणनीति' के नाम पर चतुराई मिथ्या कूटनीति ही साबित हुई। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लामी नेता राजनीति में पगे हैं। उनके मतवाद में ही राजनीति अभिन्न है। उन्हें भारत पर लंबे समय शासन करने का स्मरण और अहंकार भी है। वे इसे बोलते भी हैं। अभी मौलाना मदनी ने दुनिया को एक प्रकार से यह संदेश दे दिया कि यहां मुसलमान पीड़ित और हिंदू उत्पीड़क हैं, जबकि केरल से कश्मीर और असम-बंगाल तक, बार-बार हिंसा, अपमान, संहार और विस्थापन केवल हिंदुओं को झेलना पड़ा है। यह शिकायत कौन करेगा और कब?

हिंदुओं ने झूठी कोशिशें बहुत कर लीं। एक बार सच्ची कोशिश करके देखें। मुसलमानों को भी भारत माता की संतान और अपना भाई मान व्यवहार करें। उनके मतवादी मिथ्या-अहंकार को उसकी असली जगह दिखाएं। तभी वे हिंदू नेताओं का विश्वास करेंगे। वरना वे उन्हें दुर्बल, आरामपसंद आदि समझ कर उनका, देश का और अपना भी नुकसान करते रहेंगे।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

खुद को कठघरे में खड़ा करता विपक्ष

जगमोहन सिंह राजपूत

प्रजातंत्र के सिद्धांत विपक्ष को ऐसा कोई निर्देश नहीं देते कि वह सरकार के अच्छे कामों की सराहना ही न करे

करीब एक माह पहले मोदी सरकार की ओर से अनुच्छेद 370 और 35-ए को खत्म करने के लिए जो फैसला किया गया उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का सिलसिला अभी भी कायम है। हालांकि इस फैसले का विरोध भी हो रहा है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि देश लंबे समय से इन अनुच्छेद और खासकर 370 को हटाए जाने का इंतजार कर रहा था। इसके लिए जिस साहस की आवश्यकता थी वह मोदी सरकार दिखा सकी। इसी कारण कई विरोधी नेता भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अन्य हमेशा की तरह उन पर निशाना साधने और उन्हें भला-बुरा कहने में लगे हुए हैं। ऐसे नेता मोदी के लिए सहायक ही साबित हो रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक यात्रा में उनके विरोधियों ने जो योगदान किया है उस पर कोई अध्ययन किया जाए तो यह अवश्य निकल कर बाहर आएगा कि अपने विरोधियों के एक-एक शब्द को कान-लगाकर सुनिए, उस पर विचार कीजिए और अपनी रणनीति निर्धारण में उसका उचित प्रत्युत्तर निहित करिए। मोदी की व्यक्तिगत प्रगति यात्रा में कुछ शब्दों का भारी योगदान है। जब देश ने मोदी के द्वारा गुजरात में किए गए सफल कार्यों के संबंध में जानना और ध्यान देना आरंभ किया तब उनके विपक्षी चिंतित होकर और 'अपनी सेकुलर छवि भुनाने के लिए' 'मौत का सौदागर' का हथियार बनाकर लाए। वे भूल गए कि जनता अब जनतंत्र को पहले से अधिक गहराई से समझती है और व्यवहार में सूक्ष्म दृष्टि से उसे परखती है। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का लाभ गुजरात में घर-घर पहुंच चुका था, उसकी आभा में 'मौत का सौदागर' उसके झंडाबरदारों की ओर ही बिना किसी प्रयास के पलटवार बन गया।

फिर 2014 में आए मणिशंकर अय्यर। उन्होंने दया दिखाते हुए चुनावों में हार के बाद नरेंद्र मोदी को चाय की दुकान खोलने की पेशकश की और शुरू हो गई 'चाय पर चर्चा' जो देश के हर गांव, गली-कूचे तक पहुंची। मणिशंकर को पाकिस्तान जाकर कहना पड़ा कि मोदी को हटाने में मदद कीजिए। यह राष्ट्र के लिए लज्जाजनक था और लोगों ने इसे भुलाया नहीं। अन्य भी कई थे जो लगातार आत्माघाती गोल करते जा रहे थे, मगर ईर्ष्या और सत्ता में लौटने की जल्दी में इसे समझ ही नहीं पाए। 2019 के चुनाव परिणामों पर कई विद्वानों ने अपना-अपना विश्लेषण किया है और आगे भी करते रहेंगे, मगर मेरे जैसे लोग तो चाहेंगे कि 'चौकीदार चोर है' के नारे पर

अनेक विद्वान और विश्वविद्यालय गहन अध्ययन करें और कराएं। जब इस शब्द या धारणा का जमकर इस्तेमाल हो रहा था तब मेरी कई वरिष्ठ लोगों से चर्चा हुई। मैंने कहा कि क्या यह बोफोर्स में चोरी के आरोपों से मानसिक निजात पाने की अभिव्यक्ति तो नहीं? भारत की राजनीति और दलगत राजनीति पर तीन शब्दों-मौत का सौदागर, चायवाला और चोर का प्रभाव स्थायी है।

मोदी-विरोधी राजनीति को समझने का सबसे सरल, सटीक और सुपरिचित उदहारण हैं दिग्विजय सिंह जिन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी साख और स्वीकार्यता कहां तिरोहित हो गई। वह अभी मानते हैं कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय पटल पर पुनः उभरने और सत्ता में स्थापित होने के लिए हिंदू-मुस्लिम का भेद बढ़ाने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। उन्होंने अभी सबसे नई खोज देश के सामने रखी है कि पाकिस्तान और आइएसआइ के लिए जासूसी करनेवालों में हिंदू अधिक हैं। यह समझ पाना मुश्किल है कि यह 'दिग्विजयी सच' सामाजिक सद्भाव और पंथिक एकता बढ़ाने में कैसे सहायक होगा? इस सारे संदर्भ में आशाजनक स्थिति यह है कि नरेंद्र मोदी के संबंध में लोगों में जो आदरभाव है वह जनमानस में उन अरबपतियों पर भारी पड़ता है जिन्होंने दूध बेचकर, बैगन उगाकर, सेव बेचकर, चंदा पाकर अरबों कमा लिए, अकूत संपत्ति के मालिक हो गए और जो अब 'बदले की राजनीति' का रोना रो रहे हैं। बेनामी संपत्ति क्यों जब्त नहीं होनी चाहिए? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसों को वापस लाने के प्रयास का समर्थन क्यों नहीं होना चाहिए? तीन लाख से अधिक शेल कंपनियां बंद हुईं। क्या यह भ्रष्टाचार के विरुद्ध महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है? सरकार से कभी भी कोई भी पूर्णरूपेण संतुष्ट नहीं हो सकता है, न होना चाहिए। प्रगति और गतिशीलता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। प्रजातंत्र के सिद्धांत और व्यवहार विपक्ष को ऐसा कोई निर्देश नहीं देते हैं कि सरकार की सजीव और सफल उपलब्धियों पर निगाह ही न डाली जाए। विपक्ष कई बार ऐसा करता ही दिखता है।

नरेंद्र मोदी ने जब प्रारंभ में विदेश यात्राएं प्रारंभ कीं तो उनका हर देश में अभूतपूर्व स्वागत हुआ। इनमें वह अमेरिका भी था जिसने कभी मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को भारत के मानवाधिकार संगठनों के प्रचार के कारण वीजा देने से मना कर दिया था। वही अमेरिका नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए खड़ा था। बाद में वहां की संसद में मोदी के भाषण पर जो उत्साह दिखा वह अद्भुत और अकल्पनीय था। कुछ लोग नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि को समझ नहीं पाए और विदेश यात्राओं पर किए गए 'अनावश्यक' खर्चे का हिसाब मांगते रहे। उनकी आंखें तब भी नहीं खुलीं जब सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मालदीव, बहरीन जैसे देशों ने भी नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान दिए। इसी क्रम में अभी हाल में रूस ने भी उन्हें सम्मानित किया है।

अनुच्छेद 370 और 35-ए के हटाए जाने के बाद विश्वभर में पाकिस्तान के प्रलाप का प्रभाव नगण्य कर पाना किसी दूरगामी रणनीतिक चिंतन की ही उपलब्धि हो सकती है। आज भी जम्मू-कश्मीर की स्थिति को लेकर कुछ जाने-पहचाने लोग देशहित को भुलाकर व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के आधार पर भ्रम फैलाने तक ही अपने को सीमित कर रहे हैं और अपने शब्दों से पाकिस्तान के खिलौना बन रहे हैं। इसका उदाहरण तब मिला जब जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाने के क्रम में राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला के बयानों का सहारा लिया।

(लेखक एनसीईआरटी के निदेशक रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सेवा

सेवा कार्य कभी खाली नहीं जाता है। उसका फल कभी-न-कभी जरूर मिलता है। किसी को शीघ्र ही सेवा का फल मिल जाता है तो किसी को थोड़ी देर लगती है। यह उनके कर्म पर निर्भर करता है। कर्म करके ही भाग्य को मजबूत बनाया जाता है। इसलिए सेवा करने से कभी मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा देख रहा है। वे सही का सही और गलत का गलत न्याय करने वाले और फलदाता सर्वोच्च न्यायाधीश की भूमिका निभाते हुए दंड और कृपा का उपहार, पारितोषिक के रचयिता और दाता हैं। भगवान की सेवा में श्रद्धा-भाव से की गई मजदूरी कभी कम नहीं मिलती है। वह वृक्षों के फल की तरह असंख्य रूप में धन, यश, कीर्ति, आयु, सम्मान के रूप में प्राप्त होकर ही रहती है।

जो बोते हैं, उन्हीं को काटने का अवसर भी प्राप्त होता है और जो जैसा बोते हैं, उसी के अनुसार उन्हें वृक्षों के फल चखने के लिए प्राप्त होते हैं। आम का वृक्ष लगाने वाले को कभी बबूल नहीं प्राप्त होता है। आम बोने वाले को स्वादिष्ट फल ही प्राप्त होता है, पर बबूल बोने वाले को कदम-कदम पर कांटों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख-दुख, लाभ-हानि का परिणाम मनुष्य को बोने और काटने के सिद्धांत की कसौटी पर आधारित है। बोना-काटना क्रिया की प्रतिक्रिया के वैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध करती है। जो अच्छा बोएंगे तो अच्छी फसल काटेंगे और जो बुरा बोएंगे तो बुरी ही फसल काटेंगे। बोने-काटने का सिद्धांत एक हाथ से लेने और देने की तरह है। प्यार देने वाले प्यार पाते हैं और घृणा-द्वेष करने वाले घृणा-द्वेष पाते हैं।

अपनी भावना को सुंदर बनाना जीवन को परम कल्याणकारी मार्ग पर प्रशस्त करना होता है। स्वर्ग-नरक, सुख-दुख अच्छा-बुरा बोने और काटने के वैज्ञानिक तथ्य को सिद्ध करता है। अच्छे-बुरे कर्मों का फल निश्चित रूप से निज जीवन में ही मिलता है। इसलिए जीवन को परमात्मा का उपहार मानकर उन्हीं की सेवा में समर्पित करना जीवन जीने का अभिप्राय है।

मुकेश ऋषि

बच्चों को बचाने की पहल

मीनाक्षी भटनागर

> बाल पोर्नोग्राफी और बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा कंटेंट पूरी दुनिया के लिए एक दंश बना हुआ है। इन पर रोक जरूरी है

पिछले महीने ऑनलाइन बाल पॉर्नोग्राफी और बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े किसी भी विषय के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ। इस पर बनी सहमति को एक सराहनीय पहल कहा जा सकता है। इस मामले में भारत की ओर से राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी और अमेरिका स्थित गुमशुदा एवं शोषित बच्चों के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एनसीएमइसी) ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों एक बीच हुई यह सहमति बाल पॉर्नोग्राफी एवं बाल यौन शोषण संबंधी सामग्रियों के संबंध में जानकारियां साझा करने के लिए नया तंत्र स्थापित करने में मददगार होगी। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की राह आसान होगी। कानून प्रवर्तन एजेंसियां साइबर जगत से बाल पोर्नोग्राफी एवं बाल यौन शोषण सामग्री को भी हटा सकेंगी।

दरअसल बाल पोर्नोग्राफी और बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़ा कंटेंट पूरी दुनिया के लिए एक दंश बना हुआ है। यह अमानवीय सोच और कुत्सित विचारों का ऐसा मेल है, जो मासूम बच्चों की जिंदगी का दुश्मन बना गया है। यह बच्चों की मासूमियत पर प्रहार करता है। बावजूद इसके ऐसे साइट्स इंटरनेट पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। सबसे बड़ी मुश्किल ऐसी साइट्स पर नजर रखने की है। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि भारतीयों को इंटरनेट पर किसी भी तरह की सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए किसी साइट का भारतीय होना जरूरी नहीं है। ऐसे में हमारी प्रशासनिक या कानूनी संस्थाओं के लिए इन विदेशी वेबसाइटों की निगरानी करना मुश्किल है। साथ ही यह उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सरकार से चाइल्ड पोर्न की वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को कहा था, क्योंकि ऐसी सामग्रियां ना सिर्फ भारत में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के आंकड़ों में बढ़ोतरी कर रही हैं, बल्कि इससे बच्चों के मानवीय अधिकारों का हनन भी हो रहा है। बाल तस्करी के बढ़ते आंकड़ों के कारणों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक अहम कारण है। यही वजह है कि सरकार ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में दंडात्मक प्रावधानों में सख्ती के लिए पॉक्सो एक्ट में संशोधन कर पहले तय तीन साल की सजा को बढ़ाकर पांच साल से लेकर अधिकतम सात साल तक कर दिया है। इस संबंध में अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी गया है। हालांकि इस पर रोक लगाने के लिए विदेशों के सर्वर से ऐसी सामग्रियां हटानी सबसे जरूरी कदम है। आशा है कि इस समझौते के बाद यह काम आसान होगा।

स्मार्ट फोन और डिजिटल तकनीक के विस्तार के दौर में बाल शोषण का स्वरूप बदल गया है। मानसिक और शारीरिक शोषण के नए तरीके बच्चों के लिए दंश बन गए हैं। जरूरी है कि ऐसे कंटेंट परोसने वाली वेबसाइट्स पर ही शिकंजा कसा जाए। वर्चुअल दुनिया में सक्रिय बच्चों को भी सजग रहने की सीख दी जाए। सरकार और संस्थाओं की कोशिशें और आम लोगों की समझ भरी हिस्सेदारी ही इस शोषण पर रोक लगा सकती है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

आतंक के भय से मुक्त हो कश्मीर घाटी

राजीव सचान ने अपने आलेख 'आतंक और अन्याय की अनदेखी' में हत्या और अपहरण के आरोपी यासीन मलिक के साथ 1995 से लेकर अब तक बरती गई नरमी पर जो प्रश्न खड़ा किया है, वह अधूरा है। यासीन मलिक ही क्यों, अब तो 1990 से अब तक आतंकवादियों द्वारा की जाने वाली हर वारदात और उससे पीड़ित कश्मीरी पंडितों, सिखों तथा अन्य कश्मीरी नागरिकों के प्रति न्याय होना चाहिए। अब यासीन मलिक जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने वाले सफेदपोश नेताओं को भी बेनकाब करना जरूरी है, ताकि कश्मीर की आवाम के दिल में समाया हुआ पाक पोषित आतंकवाद का डर निकल जाए और वे निर्भीक होकर देश के इन अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में गवाही दे सकें। अभी तक खूंखार आतंकवादियों के भय से कश्मीर के शांतिप्रिय नागरिक अपनी हत्या के अंदेशे से चाहकर भी इनके विरुद्ध मुंह खोलने का साहस नहीं जुटा पाते थे। इसके लिए कश्मीर के हालात सामान्य होते ही अपनी जर-जमीन से जबरन निर्वासित किए गए कश्मीरी पंडितों और सिखों को कश्मीर में पुनःस्थापित करना जरूरी है। इससे कश्मीर में विखंडित की जा चुकी उस कश्मीरियत को जीवंत करने में सहयोग मिलेगा जो कश्मीर को शेष भारत की सांस्कृतिक चेतना से जोड़ने का काम करती है। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में मात खाने के बाद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता से जो मात दे दी है, उससे कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अलगाववाद का एजेंडा चलाने वाले भारत विरोधियों का हतोत्साहित होना स्वाभाविक है। ऐसी अनुकूल स्थिति में अब इन देश विरोधी तत्वों को संरक्षण देने वाले सशक्त लोगों पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए, ताकि कश्मीर की शांतिप्रिय जनता निर्भय होकर इन आतंकवादियों के विरोध में खड़ी हो सके।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

हिंदी की महत्ता

प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन जो सम्मान हिंदी को मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण हिंदीभाषी होते हुए भी इसे बोलना पसंद नहीं करते हैं। हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं। हमें लगता है कि हिंदी माध्यम से पढ़ने पर बच्चा पिछड़ जाएगा। इसी मानसिकता की वजह से एक अरब से भी अधिक हिंदीभाषी के होते हुए भी हम अपनी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलवाने में अब तक विफल हैं। हिंदी के पुनरोत्थान के लिए राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है।

anupamyadavay943@gmail,com

देश में आर्थिक मंदी

इस समय देश में आर्थिक मंदी की सुगबुगाहट है। भारत की जीडीपी दर 5.8 फीसद से घटकर 5 फीसद पर आ गई है। कृषि विकास दर में गिरावट, निर्माण सेक्टर में गिरावट और आय सृजन, बचत एवं खपत में गिरावट इस मंदी के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। अमेरिका-चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का फायदा भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार इस संकट की घड़ी से निकलने के पुख्ता कदम उठा रही है। सरकार के प्रयास एवं देशवासियों के सहयोग से हम इस बीमारी से जल्द निजात पाएंगे।

ashish.sharma100210@gmail.com

उचित कदम

दैनिक जागरण में प्रकाशित संपादकीय विचार योग्य है। यातायात नियमों को लेकर भारत सरकार ने कम जुर्माने के साथ लोगों को नियमों का पालन करने को कहा तो कोई नहीं माना, पर वहीं जब जुर्माने बढ़ा दिए गए तो नियमों का पालन होने लगा। नियमों का पालन सरकार के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जरूरी है। जुर्माने को लेकर लोगों में एक डर सा जरूर बैठ गया है, यातायात पुलिस को इसे दूर करना होगा। जुर्माना बढ़ाना-घटाना राज्यों की अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन जो सबसे उत्तम है वह है देश के नागरिकों की सुरक्षा। केंद्र सरकार की प्राथमिकता भी यही है।

shreyaa194@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: